

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 27 □ अंक- 281 □ राठपुर, मंगलवार 5 नवम्बर 2024 □ पृष्ठ- 8 □ मूल्य- 2.50 रुपये □ राठपुर □ बिलासपुर □ जादलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

राज्य अलंकरण की हुई घोषणा

नारायणपुर के बुटलू राम माथरा को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान

राठपुर, 5 नवंबर (हाईवे चैनल)। राजधानी नवा राठपुर में राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने महान चासीदास संग्रहालय परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विशेष सम्मान समारोह की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह अलंकरण सम्मान उपलब्धित जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया जाएगा।



जुड़े राज्य अलंकरण शामिल हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान बुटलू राम माथरा, यति यतनलाल सम्मान मनोहर गौशाला, खेरागढ़, गुण्डापुर सम्मान छोट्टी मेहरा, मिनीमाता सम्मान सतगौरी मणिला जगुति समिति, गुरु चासीदास सम्मान राजेंद्र गिलहरी, ठाकुर प्यारलाल सम्मान शशिदास द्विवेदी, चंदलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार प्रिंट मीडिया भोला राम सिन्हा, चंदलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहन तिवारी, पॉइंट सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉ. सत्यभामा आशिष्ठ, चक्रधर सम्मान सुभाकर रामाडिख शेखलीकर, मुसकर खेर स्मृति सम्मान, स्वास्थ्य विभाग, मनोहर लाल लहेजा, बिलास देवी केन्द्र मत्स्य विभाग पुरस्कार विनोद दास, पॉइंट लखनलाल मिश्र सम्मान, अपराध अनुसंधान, रामनरियेश यादव, खामना साव सम्मान, छात्र लोक संगीत, दुधनल कुमार हरमछु, लक्ष्मण मन्तुरिया सम्मान, छात्र लोकगीत, निर्मला ठाकुर, किशोरी साहू राष्ट्रीय अलंकरण, छात्र सिनेमा सतीश जैन, पॉइंट माधव राव सप्रै राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान अनुल जैन आदि शामिल हैं।

डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्योत्सव के आगम दिव, यानी कल, यह विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें समाज, शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल, और विज्ञान समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ सरकार बनने के बाद प्रदेश ने एक बार फिर संस्कृति लिखा है कि हमने बनाया और हम ही संवरेंगे। राज्योत्सव समारोह के समापन पर 36 अलंकरण उपलब्धित जगदीप धनखड़ के हाथों दिए जाएंगे। इसमें 16 अलग-अलग विभागों से

पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट अंग्रेजी मुकेश एस सिंह, धनंतीर सम्मान, स्वास्थ्य विभाग, मनोहर लाल लहेजा, बिलास देवी केन्द्र मत्स्य विभाग पुरस्कार विनोद दास, पॉइंट लखनलाल मिश्र सम्मान, अपराध अनुसंधान, रामनरियेश यादव, खामना साव सम्मान, छात्र लोक संगीत, दुधनल कुमार हरमछु, लक्ष्मण मन्तुरिया सम्मान, छात्र लोकगीत, निर्मला ठाकुर, किशोरी साहू राष्ट्रीय अलंकरण, छात्र सिनेमा सतीश जैन, पॉइंट माधव राव सप्रै राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान अनुल जैन आदि शामिल हैं।

लोहारीडीह कांड की होगी एसआईटी जांच एडिशनल एसपी पटेल करेंगे नेतृत्व

कवर्धा, 5 नवंबर (हाईवे चैनल)। कवर्धा जिले के लोहारीडीह कांड को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। लोहारीडीह में हुए हत्याकांड की गहन जांच के लिए राज्य सरकार ने (विशेष जांच टीम बन दी है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम इस मामले की जांच को शुरू करेगी। इस टीम के गठन के साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी जारी है, जिसकी रिपोर्ट 20 नवंबर तक प्रस्तुत की जाएगी।

आपको बता दें कि उधर इस मामले में लोहारीडीह के ग्रामीणों ने राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा से गुलाकांत कर कई लोगों के निधियों का दावा किया है। ग्रामीणों के अनुसार, ग्रामीणों के 167 लोगों के फिलहाल 1 फ, एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 69 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं। जबकि एक आरोपी प्रशान्त साहू को जेल में भी छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने कुछ गिरफ्तार लोगों के निधियों को भी दावा करी है।



हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 5 नवंबर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक निजी संपत्ति संसाधन को संचिधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत भीमति संसाधन नहीं कहा जा सकता है। नौ जजों की पीठ में जस्टिस इरिफेकर राय, कोवी नारगा, जेजी पारदीवाला, सुभाष पुलिया, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद शर्मा और ऑस्टीन जॉर्ज मंडवह भी शामिल थे।



9 जजों की संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला

सोईआई चंद्रचूड़ ने कहा कि तीन जजमेंट हैं, मेरा और 6 जजों का। जस्टिस नारगा का आंशिक समर्थित वाला और जस्टिस संबिंध एक संदर्भ पर सुनवाई की।

धुलिया का असहमति वाला। पीठ द्वारा 1 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के प्रत्येक निजी संसाधन को मनुष्य के भौतिक संसाधन के हिस्से के रूप में रखा दूर की कोड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उन निवेशकों को भी डरा देगा जो उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर से सावधान होंगे। यह टिप्पणी तब आई जब वरिष्ठ अधिकार गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि विभिन्न संविधान पीठों के 16 फैसलों में निजी संपत्ति और निजी संसाधनों को शामिल करने के लिए भौतिक संसाधनों की लगातार व्याख्या की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित एक संदर्भ पर सुनवाई की।

संसाधनों की लगातार व्याख्या की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित एक संदर्भ पर सुनवाई की।

ब्रेकिंग न्यूज

केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी पर पुलिस अधिकारी को धमकाने का मामला दर्ज

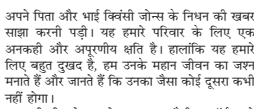
नई दिल्ली, 5 नवंबर (न्यूज चैनल)। केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के खिलाफ खनन के एक मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को धमका देने के आरोप में केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मनीरीधक एम. चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर आरोपों को मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप है कि कुमारस्वामी ने एक सरकारी कर्मचारी को उसके कार्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए उसे धमकाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि अधिकारी खनन के एक मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कुमारस्वामी आरोपी हैं। कुमारस्वामी के खिलाफ जांच उन आरोपों से संबंधित है। जिसमें उन्होंने 2006 से 2008 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कानून का उल्लंघन करते हुए बेखोरी जिले में श्री साईं वेंकटेश मिराल्ल (एसएसवीएम) को 550 एकड़ को खनन पट्टा अवैध रूप से खींचा किया था। चंद्रशेखर ने खनन पर धान में दर्ज अनौपचारिक शिकायत में कहा, "एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार करने और आरोपी (कुमारस्वामी) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पचास सप्ताह और सामग्री मिलने के बाद 21.11.2023 को कर्नाटक के महाप्रतिपक्ष रामचंद्र को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था।



चूरा- सुनती हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार हर निजी संपत्ति को अधिग्राह नहीं कर सकती। चुरिहा- हांजी, एक लकड़वा जो चला सकती है न...

माइकल जैक्सन को सुपरस्टार बनाने वाले क्विन्सी जोन्स नहीं रहे

नई दिल्ली, 5 नवंबर (न्यूज चैनल)। माइकल जैक्सन को सुपरस्टार बनाने वाले दिग्गज क्विन्सी जोन्स का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। क्विन्सी जोन्स की मीत से हॉलिवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। माइकल और जोन्स की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जोन्स ने जैक्सन के साथ मिलकर कई हिट एल्बम बनाई, जिनमें बिलर जैसे एल्बम शामिल हैं, जो आज भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। जोन्स के करीबी मित्र अनिलोड रॉबिन्सन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि किसी जोन्स का निधन रिवरवा रात को हुआ, जब वह अपने घर में थे।



28 ग्रैमी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया

क्विन्सी जोन्स के परिवार ने भी उनके निधन के बाद एक बयान जारी कर कहा- आज रात भी लेकिन टूटा हुआ दिल लेकर हम उनको रचनाएँ आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।

एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र को लूटने आए आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली, मौत

जसपुर, 5 नवंबर (हाईवे चैनल)। राजधानी राठपुर में गोलीकांड के बाद जसपुर से भी गोलीबारी की एक और घटना सामने आई है। जसपुर के कांसवाल थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने लुट की नींव से बुजुर्ग महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं बुजुर्ग के नती को भी बेदम पीटा है। आरोपियों ने घटना को दिनदहाड़े अंजाम दिया है।

जानकारी के मुताबिक, घटना कांसवाल थाना के ग्राम पंचायत बड़ाईकेला गांव की घटना है। अब से कुछ देर पहले दो बदमाश लुट की नियत से ग्राहक सेवा केंद्र एसबीआई बैंक संचालक को दुकान में पहुंचे। इस दौरान दोनों आरोपी दुकान संचालक से लुट करने लगे। लुट का विरोध करने पर दोनों बदमाशों ने दुकानदार युवक को बेदम पीटा। नाती को मार खाता देख बुजुर्ग दादी बीच-बचाव के लिए पहुंची तो बदमाशों ने उस पर दानव गोली चला दी। इस घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। विरहवाडी गोलीकांड की घटना से इलाके में हड़बुल मचा हुआ है। आरोपी पुलिस को पकड़ से बाहर है,



बेदम पीटा। नाती को मार खाता देख बुजुर्ग दादी बीच-बचाव के लिए पहुंची तो बदमाशों ने उस पर दानव गोली चला दी। इस घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। विरहवाडी गोलीकांड की घटना से इलाके में हड़बुल मचा हुआ है। आरोपी पुलिस को पकड़ से बाहर है,

सरकारी कर्मचारियों के परिवार को बड़ी राहत अब बेटी का नाम भी शामिल करना अनिवार्य

नई दिल्ली, 5 नवंबर (न्यूज चैनल)। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन से जुड़े नए नियम जारी किए गए हैं। पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब परिवार पेंशन से प्राप्त सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकेगा। इसके अलावा, एक्सट्राऑर्डिनरी पेंशन के तहत मिलने वाले सभी रिटायरमेंट बेंचिफिट को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पेंशन में बेटी का नाम शामिल करने के कई मामले सामने आते रहे हैं। इसे रोकने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन फॉर्म में बेटी का नाम अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। केंद्रीय सचिव सेवा (पेंशन) निगम, 2021 के तहत, सीतेली और गोद ली गई बेटियों के साथ-साथ अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को भी परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए सभी का नाम पेंशन रिकॉर्ड में जोड़ा जाना चाहिए। नए नियमों के तहत, पेंशन पर पहला हक विकलगा बच्चे का होगा। अगर परिवार में कोई बच्चा शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, सामान्य स्थिति में बेटी को तब तक फैमिली पेंशन मिल सकती है जब तक वह शादी नहीं कर लेती या आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं हो जाती। यदि बेटियाँ 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित, तलाकशुदा, या विधवा हैं, तो उन्हें परिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकता है।

इस शर्त के तहत, परिवार के अन्य सभी बच्चे 25 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए और उनके पास कोई आय स्रोत होना चाहिए।

रूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने हार्द कोर्ट के फैसले को किछा खारिज

रूपी में संचालित 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट उच्च प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 संवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें कि मार्च 22 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। इससे हुए ही आदेश दे दिया था कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को साधारण स्कूलों में नामांकन दाखिल कराया जाए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ मदरसा संचालकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्याय मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा।

अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल

नई दिल्ली, 5 नवंबर (न्यूज चैनल)। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को यानी आज (5 नवंबर) अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। राहुल चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतरें और सड़क मार्ग से अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के लिए रवाना हो गए। अपने इस दौरे पर वह जिला विकास समन्वय और निर्गामी समिति (दिगम) की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।



मिली जानकारी के मुताबिक, रायबरेली पहुंचकर राहुल ने नगर निगम द्वारा डिप्टी कॉलेज चौहान पर किए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। राहुल की मां सोनिया गांधी लगातार 5 बार रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। इस बार उनके लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद राहुल इस सीट से चुनाव मैदान में उतरें और बड़े अंतर से जीत हासिल की। अमेठी और वायनाड (केरल) से सांसद रह चुके राहुल का रायबरेली से सांसद के रूप में यह पहला कार्यका है। हालांकि अपनी मां के लंबे समय से प्रतिनिधित्व के कारण वह पिछले कुछ वर्षों में अक्सर इस क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटारटमेंट से पहले कई सुलगत सवालों के लिए जोरदार जवाब

नई दिल्ली, 5 नवंबर (न्यूज चैनल)। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मजबूत अंतर-संस्थागत तंत्र के तहत होता है और दोनों की अधिकारिकता आवास पर आजने से कुछ भी गलत नहीं था

एक कार्यक्रम में कहा कि इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद गोपनीय पृष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उनके मजबूत अंतर-संस्थागत तंत्र के तहत होता है और दोनों की अधिकारिकता आवास पर आजने से कुछ भी गलत नहीं था

दूसरे से मिलेंगे नहीं। दूसरे कहा, शक्तियों के पृष्ठभूमि की आधारणा का यह अर्थ नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इस भावना में एक-दूसरे से अलग हैं कि वे मिलेंगे नहीं या तर्कसंगत संवाद नहीं करेंगे। राज्य में, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की मुख्यमंत्री से मिलने और मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने का एक प्रोटोकॉल है। इनमें से अधिकतर बैठकों में बजट, बुनियादी हिस्सा है।

सोईआई चंद्रचूड़ ने 'इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद गोपनीय पृष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उनके मजबूत अंतर-संस्थागत तंत्र के तहत होता है और दोनों की अधिकारिकता आवास पर आजने से कुछ भी गलत नहीं था



प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मजबूत अंतर-संस्थागत तंत्र के तहत होता है और दोनों की अधिकारिकता आवास पर आजने से कुछ भी गलत नहीं था